

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2024

(उत्तराखण्ड विधेयक संख्या-.....वर्ष, 2024)

उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) में उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में अग्रेत्तर संशोधन करने के लिए,

विधेयक

भारत गणराज्य के पञ्चहत्तरवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : -

- |                           |    |  |
|---------------------------|----|--|
| संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ | 1. | (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) अधिनियम, 2024 है।<br>(2) यह तुरन्त प्रवृत्त होगा।  |
| धारा 2 में संशोधन         | 2. | उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (जिसे यहां आगे मूल अधिनियम कहा गया है ) की धारा 2 में खण्ड (51-क) के पश्चात् खण्ड (51-ख ) निम्नवत् अन्तःस्थापित कर दिया जाएगा, अर्थात्-<br>“(51-ख) “समर्पित आयोग” से तात्पर्य, राज्य सरकार द्वारा अन्य पिछड़ा वर्ग की सीटों को अवधारित किये जाने हेतु गठित समर्पित आयोग से है;”  |
| धारा 7 में संशोधन         | 3. | मूल अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दी जाएगी, अर्थात्-<br>“(1) प्रत्येक निगम में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और पिछड़े वर्गों के लिए स्थान आरक्षित किये जायेंगे और इस प्रकार आरक्षित स्थानों की संख्या का अनुपात निगम में प्रत्यक्ष चुनाव से भरे जाने वाले कुल स्थानों की संख्या में यथाशक्य, वही होगा जो नगर निगम क्षेत्र में अनुसूचित जातियों की या नगर निगम क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का अनुपात ऐसे क्षेत्र की कुल जनसंख्या में हो और पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या वही होगी जो समर्पित आयोग द्वारा समसामयिक गहन अनुभवजन्य जांच के आधार पर की गई अनुशंसा के अनुसार राज्य सरकार निर्धारित करेगी और ऐसे स्थान किसी निगम में विभिन्न कक्षाओं को चक्रानुक्रम द्वारा ऐसे क्रम में, जैसा नियमों द्वारा विहित किया जाए, आवंटित किये जा सकेंगे।”<br>किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं पिछड़े |

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी  
विधान सभा सचिवालय  
उत्तराखण्ड

वर्गों के लिए आरक्षण कुल स्थानों की संख्या के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा;

किन्तु प्रतिबन्ध यह और कि अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों का आरक्षण की कुल संख्या के 50 प्रतिशत या उससे अधिक होने पर पिछड़े वर्गों के लिए कोई आरक्षण नहीं होगा;

किन्तु प्रतिबन्ध यह और भी कि यदि पिछड़े वर्गों की जनसंख्या के आंकड़े उपलब्ध न हो तो नियमों द्वारा विहित रीति से सर्वेक्षण करके उनकी जनसंख्या अवधारित की जा सकती है,"

धारा 25 का 4. मूल अधिनियम की धारा 25 के खण्ड (ठ) को निम्नवत प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात्-

"(ठ) उसकी दो से अधिक जीवित संतान है, जिनका जन्म दिनांक 27 अप्रैल, 2003 के पश्चात् हुआ है;

परन्तु पहली संतान के बाद दूसरे गर्भधारण पर जुड़वा बच्चे या उससे अधिक होने पर अनर्हता सम्बन्धी उक्त प्राविधान लागू नहीं होगा; या,"

निरसन  
व्यावृत्ति

और 5.

(1) उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) अध्यादेश, 2024 एतद्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई समझी जाएगी।

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी  
विधान सभा सचिवालय  
उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2024 प्रवर समिति  
द्वारा यथासंस्तुत।

1. प्रवर समिति की विभिन्न बैठकों में अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु राजनैतिक आरक्षण का निर्धारण किये जाने सम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्गत आदेशों, दिशा-निर्देशों पर चर्चा की गयी जिसमें समिति द्वारा भूतपूर्व न्यायाधीश श्री बी०एस० वर्मा, न्याय विभाग के अधिकारी, शहरी विकास विभाग के अधिकारियों को भी समय-समय पर चर्चा में सम्मिलित किया गया।
2. प्रवर समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि प्रस्तुत विधेयक- उत्तराखण्ड- (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) विधेयक, 2024 में प्रस्तावित संशोधन संवैधानिक व्यवस्था एवं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुसार ही प्रस्तावित किया गया है। समिति उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959) (संशोधन) विधेयक, 2024 को यथावत् पारित करने की सर्वसम्मति से संस्तुति करती है।
3. समिति यह भी संस्तुति करती है कि भविष्य में अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु राजनैतिक आरक्षण का निर्धारण माननीय सर्वोच्च न्यायालय की अनुसंशा अनुसार समर्पित आयोग द्वारा किया जाये। अन्य पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या के आंकड़ों का सर्वेक्षण रैपिड सर्वे से करवाने हेतु शहरी विकास विभाग नियमावली तैयार करें। नियमावली में इस बात का विशेष ध्यान रखा जाये कि उत्तराखण्ड राज्य के निवासियों के हितों का संरक्षण सुनिश्चित हो। राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग के उन्हीं निवासियों को रैपिड सर्वे में सम्मिलित किया जाये जो राज्य में सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण की पात्रता रखते हों।
4. समिति यह भी संस्तुति करती है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों को प्रमाण-पत्र निर्गत करने के जो मानक है, उनमें बहुत सी विसंगतियां हैं। उन विसंगतियों को दूर करने की आवश्यकता है। इसके लिये सरकार एक स्पष्ट सुविचारित नियम बनाए।

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी  
विधान सभा सचिवालय  
उत्तराखण्ड

## उद्देश्य और कारणों का कथन

शहरी स्थानीय निकाय निर्वाचन में अन्य पिछड़ा वर्ग को समुचित प्रतिनिधित्व प्रदान किये जाने हेतु गठित एकल समर्पित आयोग की संस्तुतियों के क्रम में उत्तराखण्ड (उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959) (संशोधन) अध्यादेश, 2024 प्रख्यापित किया गया है।

2- प्रस्तावित विधेयक उक्त अध्यादेश का प्रतिस्थानी विधेयक है।

प्रेम चन्द अग्रवाल  
मंत्री

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी  
विधान सभा सचिवालय  
उत्तराखण्ड

**The Uttarakhand (Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959)  
(Amendment) Bill, 2024  
(Uttarakhand Bill No.....Year, 2024)**

**A  
Bill**

further to amend the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959  
(Adaptation and Modification order, 2002) in the context of Uttarakhand State,

Be it enacted by the Uttarakhand State Legislature in the Seventy-fifth  
year of the Republic of India as follows:-

**Short title and commencement.** 1. (1) This Act may be called the Uttarakhand (Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959) (Amendment) Act, 2024

(2) It shall come into force at once.

**Amendment of Section 2** 2. In section 2 of the Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959 (Adaptation and Modification order, 2002) (hereinafter referred to as the principal Act) after clause 51-A clause 51-B shall be inserted as follows, namely: -

“(51-B) ‘Dedicated Commission’ means the Dedicated Commission constituted by the State Government to determine the seats of other Backward Classes;”

**Amendment of section 7** 3. In the principal Act sub section (1) of section 7 shall be substituted as follows, namely;

“(1) In every corporation, seats shall be reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Backward Classes and the number of seats so reserved shall bear the same proportion to the total number of seats to be filled by direct election in the corporation as the population of Scheduled Castes in the municipal corporation area or of the Scheduled Tribes in the

**प्रमाणित प्रति**

C  
लोक सूचना अधिकारी  
विधान सभा सचिवालय  
उत्तराखण्ड

municipal corporation area bears to the total population of the such area and the number of seats reserved for backward classes shall be such as determined by the State Government as per the recommendation made by the Dedicated commission on the basis of contemporary, in depth empirical investigation and such seats may be allotted by rotation to different wards in a corporation in such order as may be prescribed by rules:

Provided that the reservation for Scheduled Castes and Scheduled Tribes and Backward Classes shall not exceed 50 percent of total number of seats:

Provided further that if the total number of reservation for Schedules Castes and Scheduled Tribes is 50 percent or more, there shall be no reservation for the Backward Classes:

Provided also that if the data of population of Backward Classes is not available, then their population may be determined by conducting a survey in the manner prescribed by rules.”

**Amendment of 4.  
Section 25**

In principal Act clause (1) of section 25 shall be substituted as follows, namely: -

“(1) has more than two living children, who were born after April 27, 2003;

Provided that the above provision regarding disqualification shall not apply in case of having twin or more children in the second pregnancy after the first child; or,”

प्रमाणित प्रति

C  
लोक सूचना अधिकारी  
विधान सभा सचिवालय  
उत्तराखण्ड

**Repeal and Saving** and 5. (1) The Uttarakhand (Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959) (Amendment) Ordinance, 2024 is here by repealed.

(2) Notwithstanding such repeal anything done or any action taken under the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act.

प्रमाणित प्रति

लोक सूचना अधिकारी  
विधान सभा सचिवालय  
उत्तराखण्ड

**Statement of Objects and Reasons**

To provide adequate representation to the Other Backward Classes in the Urban Local Bodies elections as per the recommendations of the Single Dedicated Commission the Uttarakhand (Uttar Pradesh Municipal Corporation Act, 1959) (Amendment) Ordinance, 2024 has been promulgated.

2- The proposed bill is the replacing bill of the said Ordinance.

**Prem Chand Aggarwal**  
Minister

प्रमाणित पति

C  
लोक सूचना अधिकारी  
विधान सभा सचिवालय  
उत्तराखण्ड